लेखा·योग

132. स्वैच्छिक संगठनों की वित्तीय जवाबदेही - 4

Dec-06/ रा.मार्गशीर्ष १९२८: Released: फरवरी 2009

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

इस अंक में

गैर जवाबदेही का इतिहास • खामी कहां है? पृष्ठ 1

एनपीओ उत्तरदायित्व का मॉडल? • जटिलता • रखरखाव लागतें पृष्ठ 2

उद्देश्य • सिर्फ आत्मा पृष्ठ 3

लेखा योग 131 से आगे...

गैर जवाबदेही का इतिहास

कॉरपोरेट इतिहास में, साउथ सी बबल (1694-1722 ई.) उत्तरदायित्व के क्षेत्र की शुरुआती विफलताओं में से एक थी। फलस्वरूप, ब्रिटिश सरकार ने कुछ ऐसे इंतज़ाम किये जिस से कि इस तरह की घटना दोबारा न घटे। उसी प्रकार, 1930 के दशक में आयी महामंदी से सबक सीखते हुए, अमेरीकी सरकार ने 1934 में यूएस सिक्योरिटीज़ ऐण्ड एक्सचेंज कमीशन का गठन किया। लेकिन समस्या है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। हाल ही में एनरॉन घोटाले के बाद सरबेंस-ऑक्सले अधिनियम, २००२ बनाना पड़ा।

न्यू यॉर्कर[1] नामक पत्रिका के एक दिलचस्प लेख में, जॉन केसिडी ने कार्यकारी क्षतिपूर्ति और जवाबदेही के संबंध पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया है। 'दि ग्रीड साइकिल' नामक इस लेख का निष्कर्ष है कि प्रबंधकीय उत्तरदायित्व की समस्या का हर नया समाधान प्रबंधकों को उसी समाधान से बच निकलने के और भी रचनात्मक तरीके ढूंढने की प्रेरणा देता है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व के, चार सौ साल के इतिहास से हम क्या सबक निकाल सकते हैं? इस लंबे अनुभव का सबक बहुत सीधा हैः कॉरपोरेट मॉडल विफलताओं की आशंका से मुक्त नहीं हो सकता।

इस मॉडल के पीछे लेखाकारों, विश्लेषकों, ऑडिटरों और नियामकों (Regulators) की एक पूरी फौज मुस्तैदी से लगी रहती है। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र हर साल बेहिसाब पैसा खर्च करता है। परंतु पानी की तरह पैसा बहाये जाने के बावजूद भी इसकी स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा है।

खामी कहां है?

तो फिर इस मॉडल में कमी कहां रह जाती है? कहना मुश्किल है लेकिन कारोबार जगत में एक शब्द चलता है 'आत्माहीन निगम' (Soulless Corporation)। शायद यह शब्द इस गुत्थी को सुलझा सके। कंपनी के पास न तो कोई आत्मा होती है और न ही कोई अन्तरात्मा। कंपनी को न तो पाप के तराजू में तौला जा सकता है और न ही वह कर्मों का संचय करती है। न ही उसे मोक्ष या मुक्ति की कामना होती है। वह तो बस सदा-सर्वदा के लिए मुनाफा बनाते

रहना चाहती है। और अब २००८ में फिर, बहुत से बैंक जहरीले ऋणों का शिकार बन गये हैं।

कभी-कभार सीईओ या प्रोमोटर निगम के हित के लिए पूरी आत्मीयता से काम करते हैं और कंपनी को अपनी आत्मा उधार देते हैं। लेकिन ज़्यादातर मामलों में कंपनी या निगम के दोष को किसी खास अधिकारी या प्रबंधक की ज़िम्मेदारी नहीं मानी जाती है।

अक्सर अन्तरात्मा के इसी हल्केपन की वजह से, कंपनियाँ कानून की हदों को पार कर जाती हैं और वो भी हिचकिचाहट महसूस किए बिना। बल्कि कुछ विशेषज्ञों का तो मत है कि अपने शेयरधारकों की संपन्नता को बढ़ाने के लिए कंपनी अपनी कानूनी सीमाओं के भीतर रहते हुए कुछ भी कर सकती है और उसे करना भी चाहिए। इसी सोच से प्रेरणा लेते हुए कंपनियाँ कानून के साथ आंख मिचौली खेलती हैं। अपने हितों की पूर्ति के लिए, कंपनियाँ अपने कानून और लेखांकन मानकों की पुनर्व्याख्या करने वाले विशेषज्ञों को भारी-भरकम फीस भी देती हैं।

[1] पृष्ठ 64-77, *दि न्यू यॉर्कर,* 23 सितंबर 2002.

www.AccountAid.net

एनपीओ उत्तरदायित्व का मॉडल?

एनपीओ उत्तरदायित्व का मॉडल कैसा दिखना चाहिए? ये कहना मुश्किल है। बल्कि ये कहना ज़्यादा आसान है कि वह मॉडल कैसा नहीं दिखना चाहिए!

जटिलता

मिसाल के तौर पर, ये कल्पना करना मुश्किल है कि एनपीओ मॉडल भी उतना ही जटिल हो जितना जटिल कॉरपोरेट मॉडल होता है। एनपीओ मॉडल के लिये कॉरपोरेट मॉडल जितने संसाधनों की व्यवस्था कर पाना बहुत मुश्किल है।

रख-रखाव लागतें

इसके बाद यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि इस तामझाम का खर्चा कौन उठाएगा। ज़्यादातर सरकारें सोसायटी रजिस्ट्रार या चैरिटी कमिश्नरों पर इतना सारा पैसा खर्च नहीं करना चाहतीं। वे चाहतीं हैं कि अपने नियमन के लिए एनपीओ क्षेत्र खुद अपनी गांठ से पैसा निकाले। महाराष्ट्र और गुजरात में एनपीओ संगठन, चैरिटी

मालगुड़ी का रजिस्ट्रार

जब हम रजिस्ट्रार के कमरे में दाखिल हुए तो वहां फाइलों के अलावा कुछ दिखायी नहीं पड़ रहा था। फर्श पर, मेजों पर, कुर्सियों पर, सब जगह बस फाइलों के अंबार लगे थे। दीवारें भी फाइलों से अंटी पड़ी थीं। कहने का मतलब ये कि उस कमरे में सब तरफ सिर्फ फाइलें थीं - सिवाय छत के। जैसे-तैसे हमने रजिस्ट्रार को भी ढूंढ ही निकाला जो फाइलों के पीछे पूरी तरह छिप चुका था।

उन्होंने हमें अपने दफ्तर के काम करने के तौर-तरीकों के बारे में कई अहम बातें बतायीं। पता चला कि उनका दफ्तर कंपनियों और सोसायटियों, दोनों के पंजीकरण करता है। दफ्तर में लगभग 20 लोग हैं। हालांकि वह रजिस्ट्रार हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि पूरे राज्य में कुल कितनी सोसायटियां हैं। उनका अंदाज़ा है कि पूरे राज्य में तकरीबन 50,000 सोसायटियां होंगी। क्या पता उससे ज्यादा भी हों!

हर सोसायटी को सालाना अपने खाते जमा करवाने पड़ते हैं। खाते जमा कराने के लिए फाइलिंग शुल्क भी सोसायटी को ही देना पड़ता है। इतना ही नहीं, सोसायटियों को फाइलें भी खुद ही लानी पड़ती हैं। रजिस्ट्रार दफ्तर के पास फाइल कवर खरीदने तक का पैसा नहीं है!

न ही उसके पास उन्हें रखने के लिए जगह है। इन दस्तावेजों को एक हॉल में ढेर की तरह जमा कर दिया जाता है। अगर आपने एक बार खाते जमा करा दिए हैं और आपको पावती रसीद मिल चुकी है तो आप चैन से घर जा सकते हैं। अब कोई उन्हें दोबारा ढूंढ ही नहीं पाएगा!

अब सरकार रजिस्ट्रार दफ्तर को कंप्यूटरीकृत कराने के बारे में सोच रही है। कुछ कर्मचारी इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। उन्हें डर है कि कंप्यूटरों के आने से उनकी नौकरियां छिन सकती हैं। दूसरी समस्या है, इस काम के लिए पैसे का इंतज़ाम करना।

(बेशक, मालगुड़ी नाम की जगह तो श्री आर. के. नारायण की उर्वर कल्पना में ही जीवित थी लेकिन हमने जिस जगह का ब्यौरा ऊपर दिया है उसे आप दक्षिण एशिया के किसी भी दफ्तर में देख सकते हैं।)

उत्तर (Across): 1. राजस्व 2. आत्मा 3. वित्तीय 4. करदाता 5. धार्मिक 6. उत्तरदायित्व 7. लेखांकन 8. आमदनी
(Down): 9. राष्ट्रीयकरण 10. नैतिक 11. प्रशासनिक 12. आर्थिक 13. सामाजिक

एनपीओ मॉडल के उद्देश्य भी संभवतः अलग होंगे। कॉरपोरेट मॉडल का मकसद सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना शेयरधारकों के हितों की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करना है।

कमिश्नर कार्यालय के संचालन के लिए, सालाना लगभग 2 प्रतिशत अधिभार चुकाते हैं। अन्य राज्यों में भी फाइलिंग या पंजीकरण आदि कामों के लिये लिया जाने वाला शुल्क तेज़ी से बढ़ा है।

लेकिन, विडंबना यह है कि जब वित्तीय उत्तरदायित्व का सवाल आता है तो पंजीकार और आयुक्त भी कुछ नहीं कर पाते। इसमें से ज़्यादातर तो अपने पास जमा कराए गए दस्तावेजों को ढूंढ भी नहीं पाते हैं। ज़ाहिर है ऐसी सूरत में वे किसी विश्लेषण या व्यवस्थित हस्तक्षेप की तो सोच भी नहीं सकते।

उद्देश्य

एनपीओ मॉडल के उद्देश्य भी संभवतः अलग होंगे। कॉरपोरेट मॉडल का मकसद सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाए बिना शेयरधारकों के हितों की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करना है।

एनपीओ मॉडल का मकसद इतना संकुचित नहीं हो सकता। उसे न केवल दाता एजेंसी के इरादों का सम्मान करना होता है बल्कि इस बात का भी खयाल रखना पड़ता कि सरकार की आय में कोई कमी न आए। इतना ही नहीं, उसे लाभार्थियों और व्यापक समाज के हितों को भी पूरा करना पड़ता है।

सिर्फ आत्मा

ये तब तक संभव नहीं जब तक हम कॉरपोरेट मॉडल में यहां वहां पैबंद लगाकर, अपनाते रहें। हमें एक ऐसा मॉडल विकसित करना होगा जो खर्चीला और जटिल न होते हुए भी असरदार व उपयोगी हो। इस तरह का मॉडल तभी सामने आ सकता है जब उसमें एनपीओ क्षेत्र को नियामक की तरह देखा जाए न कि नियमन की वस्तु के रूप में। और हां, कॉरपोरेट मॉडल के विपरीत इस मॉडल के रचनाकारों को यह भी ध्यान रखना होगा कि एनपीओ संगठनों के पास आत्मा भी होती है!

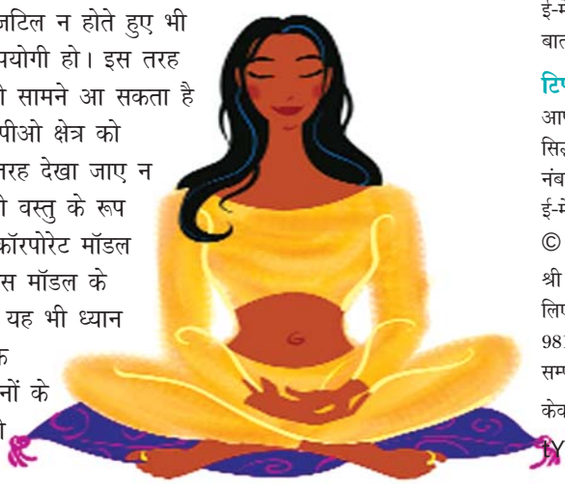

लेखा योग क्या है:

'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे 5,000 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंगेजी में लेखा-योगः

लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

कानून की व्याख्याः

यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी सामान्य स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात ज़रूर करें।

इंटरनेट पर लेखा-योगः

'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - **www.AccountAid.net.** पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए **lekhayog-subscribe@topica.com.** पर एक ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

अकाउंटएड कैप्सूलः

इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए **accountaid-subscribe@topica.com**. पर ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

इंटरनेट पर आपके खातेः

आपके खातों का सार-संकलन करके उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें आप अपनी सालाना रिपोर्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इस के उदाहरण **www.AccountAid.net**. पर देखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए **accountaid@gmail.com** पर हमें लिखें।

सवाल और स्पष्टीकरण?

अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरक. ारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियांः

आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फोन/फैक्स : 011-26343852;
ई-मेलः **accountaid@gmail.com**

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत २०६५ माघ, ईस्वी सन् फरवरी 2009.

श्री अनिल बरनवाल द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, नई दिल्ली, फोन 26811689, 9810653101 से मुद्रित। लेखः श्री संजय अग्रवाल; अनुवादः श्री योगेन्द्र दत्त सम्पादनः कु. संचिता चक्रवर्ती; डिज़ाइनः श्रीमती मोऊशुमी डे

केवल निजी प्रसार के लिए।

VT/rSC, AD/sSC/cSC/eSC/cdSA

accountable-subscribe@topica.com

परोपकार और जवाबदेही

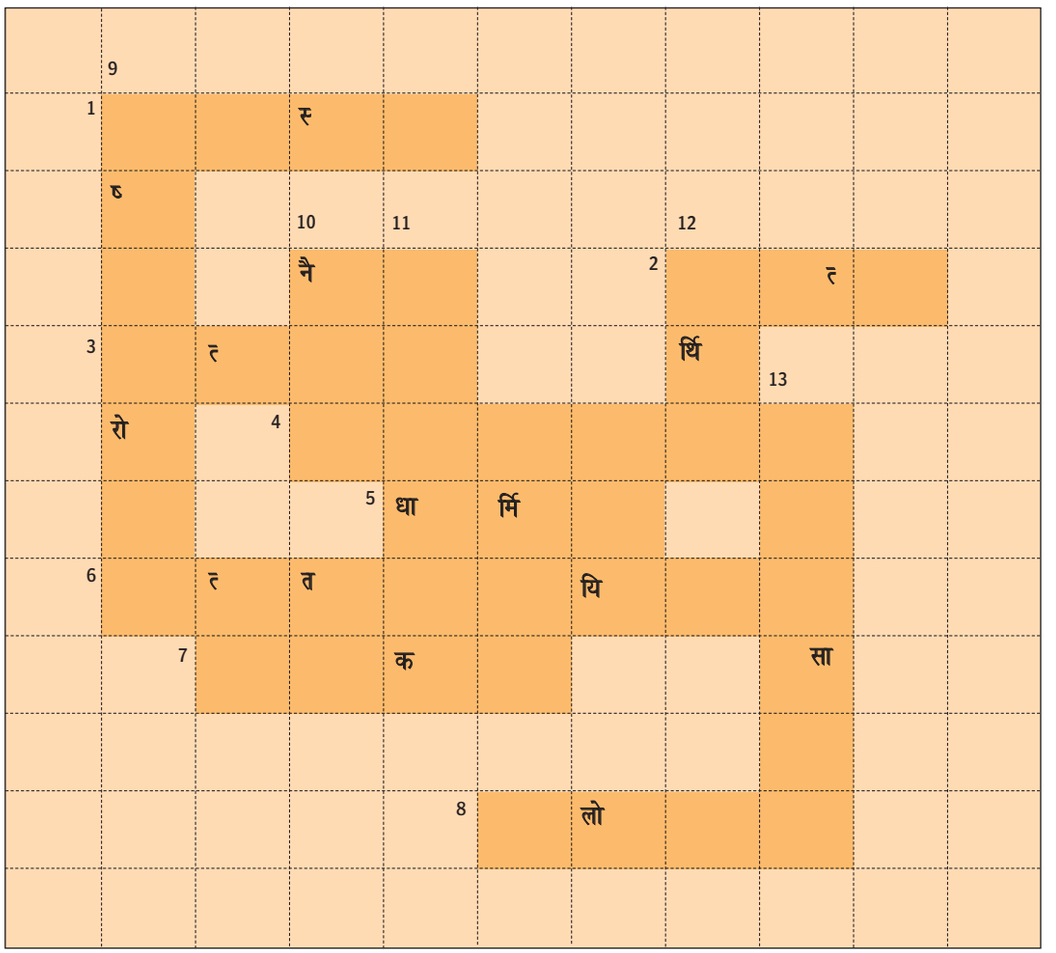

बायें से दायें (Across)

1 व्यावसायिक मॉडल में नियंत्रण सरकार के इस हिस्से की रक्षा करता है - (3.5 अक्षर)
2 कंपनी के पास यह चीज़ नहीं पर एनजीओ क्षेत्र में इसके बिना कार्य नहीं होता - (2.5 अक्षर)
3 यह जवाबदेही धनराशी का सही हिसाब किताब रहने की कला से विकसित है - (3.5 अक्षर)
4 कर चुकाने वाला - (4 अक्षर)
5 एक ऑनलाइन सर्वेक्षण के अनुसार ज़्यादातर लोग इन संस्थाओं को मिलने वाली रियायत पर रोक चाहते हैं - (3 अक्षर)
6 जन सेवी संस्थाएँ अक्सर इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं - (7 अक्षर)
7 वित्तिय जवाबदेही में धन राशि के सही उपयोग के साथ- साथ इसका भी अत्यंत महत्व है - (4 अक्षर)
8 हमें ऐसे इंसान को हमेशा अपने समीप रखना चाहिए - (4 अक्षर)

ऊपर से नीचे (Down)

9 नए एफसीआरए बिल 2006 में विदेशी अभिदाय के उपयोग में किस तरह की गतिविधियाँ रोकने के लिए ज़ोर दिया गया ह - (5.5 अक्षर)
10 जन सेवी संस्थाओं से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा की जाती है - (3 अक्षर)
11 कंपनी अधिनियम 1956ए मुख्य रूप से इन्हें सुरक्षा प्रदान करता है - (6 अक्षर)
12 एनपीओ क्षेत्र की राय लिए बिना इस मुद्दे पर कोई संवाद नहीं हो सकता - (3 अक्षर)
13 वर्तमान में एनपीओ क्षेत्र इस ढांचे में ढलता जा रहा है - (5.5 अक्षर)

(हल के लिए कृपया पृष्ठ 2 देखें।)

accountaid@gmail.com